प्रकाशनार्थ

पटना, 3 सितंबर। "अधिकारियों को धैर्यवान श्रोता होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में मौजूद अहम समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर ही सही समाधान खोजे जा सकते हैं," यह बात भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, एवं महानिदेशक, बिपार्ड ने आज यहां संपन्न हुई 'गवर्नमेंट एनालिटिक्स एंड रिफॉर्म्स' विषयक दो-दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र में विभागीय टीमों को संबोधित करते हुए कही।

"गवर्नमेंट एनालिटिक्स एंड रिफॉर्म्स" (सरकारी विश्लेषण एवं सुधार) शीर्षक से आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) द्वारा किया गया, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया कि सरकार द्वारा पहले से एकत्र किए जा रहे प्रशासनिक एवं सर्वेक्षण आंकड़ों (डेटा) का पुनः उपयोग विभागों के कामकाज को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के तरीके में सुधार लाने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है।

दिन की शुरुआत में, आद्री की सदस्य-सचिव डॉ. अश्मिता गुप्ता ने पहले दिन की कार्यवाही की मुख्य बातों का पुनरावलोकन किया, जिसमें विशेष रूप से 'उत्पादन फलन' (प्रोडक्शन फंक्शन) की अवधारणा पर बल दिया गया। उन्होंने विद्युतीकरण एवं सड़क निर्माण क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि इन क्षेत्रों में हुई प्रगति निर्गत (आउटपुट) एवं परिणाम (आउटकम), दोनों ही दृष्टि से स्पष्ट रूप से दर्ज है। उन्होंने बिहार सरकार के अभिलेखों को सबूत के तौर पर पेश किया। इसके पश्चात एक प्रश्नोत्तरी (क्विज़) आयोजित की गई, जिसमें विभागीय टीमों ने उत्पादन फलन के विभिन्न तत्वों – निवेश (इनपुट), प्रबंधन प्रथाओं, अग्रिम पंक्ति (फ्रंटलाइन) व्यवहार, निर्गत एवं परिणाम– के संबंध में अपनी समझ को परखा। आद्री के कार्यक्रम निदेशक डॉ. निरज प्रकाश ने प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कर विजेताओं की घोषणा की, जिन्हें सत्र के अंत में सम्मानित किया गया।

इसके बाद 'समस्या-प्रेरित पुनरावृत्त अनुकूलन' (प्रॉब्लम ड्रिवन इटरेटिव अडैप्टेशन - पीडीआईए) दृष्टिकोण पर एक व्याख्यान हुआ, जिसे आद्री और लंदन स्कूल आॅफ इकोनाॅमिक्स एण्ड पाॅलिटिकल साइंस (एलएसई) के संयुक्त अध्ययन के सह-लेखक तथा कार्यशाला के प्रशिक्षकों में से एक, डॉ. मार्टिन हाउस, ने प्रस्तुत किया। उन्होंने समस्याओं की पहचान कर उन्हें उनके घटक भागों में विभाजित करते हुए मूल कारण तक पहुंचने के महत्व पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने किसी हस्तक्षेप की योजना बनाने की प्रक्रिया को भी रेखांकित किया – सही प्राधिकार (अथॉरिटी) की पहचान करना, उसकी क्षमता की जांच करना, तथा प्रस्तावित कार्यवाही के लिए स्वीकृति सुनिश्चित करना।

इसी रूपरेखा के आधार पर विभागीय टीमों ने तब अपने-अपने विभागों से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने में व्यतीत किया। इसके पश्चात प्रत्येक विभागीय टीम ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष अपनी समस्या का विवरण तथा आगे की कार्ययोजना साझा की।

प्रस्तुत किए गए मुद्दों में, वित्त विभाग ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जारी धनराशि हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) तैयार करने में अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को होने वाली कठिनाई को रेखांकित किया, और इसका कारण अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा खराब परिणामों की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का भय बताया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (बीबीओएसई) के प्रति जागरूकता की कमी के कारण नामांकन कम होने के मुद्दे को उठाया। इन प्रस्तुतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री चौधरी ने दोहराया कि ऐसी क्षेत्रीय स्तर की चिंताओं को धैर्यपूर्वक एवं सहानुभूतिपूर्वक सुनना ही उन्हें कम से कम समय में हल करने का केंद्रीय आधार है।

(अभिषेक प्रसाद)